Tirupati Balaji Group / Established 2009 / Ghaziabad
R.N.I No. UPBIL/2009/28691, DAVP Code: 101473

Page 8 / Price Rs. 2.00 / Ghaziabad, Sunday, 17 November 2019
Postal Registration No. UP/GBZ-80/2016-18

TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-11 Issue - 24

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad
केन्द्र एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcgzb.com

News of the Week कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार से हरी झंडी मिलने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना–एनसीपी–कांग्रेस के बीच गठबंधन की स्थिति अब धीरे–धीरे साफ होती दिख रही है। गठबंधन का प्रमुख अजेंडा किसान और विकास होगा।

Inside Ghaziabad

पेज नंबर 2
डेबिट–क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी होने पर भी नहीं...

पेज नंबर 5
Bus with private firm staff rams tractor...

TIRUPATIEYE

रिश्वत मामले में चार्जशीट पेश

गाजियाबाद : सीबीआइ ने रिश्वत लेने के आरोपित रेलवे अधिकारी के मामले में सीबीआइ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। अभी अदालत ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। मंगलवार को लिंक कोर्ट में सुनवाई के बाद तारीख लगा दी। रिश्वत कांड का मामला गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का है। सीबीआइ के लोक अभियोन अधिकारी हरिमोहन ने अदालत को बताया कि आरोपित रेलवे अधिकारी मोहम्मद रफीक हैं।

सीबीआइ इंस्पेक्टर की हुई गवाही

गाजियाबाद : सीबीआइ कोर्ट में गेल के पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिकारी के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ इंस्पेक्टर ने बयान दर्ज कराए। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तारीख लगा दी। सीबीआइ के लोक अभियोजक कुलदीप पुष्कर ने अदालत को बताया कि मूल रूप से प्रतापगढ़ निवासी आरोपित अधिकारी बीएस ओझा गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) नोएडा में विशेष कार्याधिकारी (भूमि अध्याप्ति) पर परियोजनाओं के लिए सर्वे करवाने और भूमि अधिग्रहण करने की जिम्मेदारी थी।

वाराणसी बमकांड में हुई बहस

गाजियाबाद : वाराणसी बम कांड में मंगलवार को जिला जज दिनेश शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष ने बहस किया। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने तारीख लगा दी। घटना के आरोपित वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को डासना जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया।

दिसंबर से किसी भी जिले में बनवा सकते है ड्राइविंग लाइसेंस

मूल पते पर ही पहुंचेगा डीएल, ऑनलाइन ही लाइसेंस के लिए करना होगा आवेदन

गाजियाबाद : प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर से वह किसी भी जिले से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस उनके मूल पते पर पहुंच जाएगा। अभी तक लाइसेंस बनवाने के लिए संबंधित जिले का एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। लाइसेंस बनवाने के लिए बिजनेसमैन, नौकरीपेशा लोगों को डीएल बनवाने के लिए अपने मूल पते वाले जिले में जाना पड़ता है। यह व्यवस्था दिसंबर के शुरू तक लागू हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप जिस जिले के रहने वाले हैं या जिस जिले के आपके प्रमाण पत्र बने हुए हैं, उसी जिले में जाकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। कई बार परेशान होने के बावजूद लोगों के डीएल नहीं बन पाते थे। अब ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अपने जिले से बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वह नौकरी वाले स्थान से ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय पर जाकर लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। फिंगर प्रिंट से लेकर ऑनलाइन फोटो खिंचवा सकते हैं। पहले कोई भी व्यक्ति अपने प्रमाण पत्र लेकर संभागीय कार्यालय में जाता था, तो उसे यह कहकर वापस भेज देते थे कि जिस जिले के रहने वाले हैं। उसी जिले में जाकर प्रक्रिया पूरी कराएं। उनकी मदद नहीं होती थी। लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाते थे। समय न होने के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती थी। वहीं डीएल बनने के बाद आपके मूल पते पर ही पहुंचेगा, चाहें आपने लाइसेंस किसी भी जिले में बनवाया हो। इससे कई फायदे होंगे। वाहन से घटना करने वाले व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। क्योंकि अधिकतर लोग अपने पते को बदलते रहते हैं। उसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे।

इंदिरापुरम में तीन जगह बनाया जाएगा नो पार्किंग जोन

गाजियाबाद : जीडीए ने इंदिरापुरम में सड़कों से जाम की समस्या खत्म करने के लिए तीन जगहों पर नो पार्किंग जोन बनाने का फैसला किया है। इसके लिए भीड़भाड़ वाले तीन जगहों को चिन्हित किया है। सबसे पहले शिप्रा मॉल और हैबिटेट सेंटर के बीच वाली रोड पर नो पार्किंग जोन बनाया जाएगा। इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर जीडीए गाड़ी के चालक से जुर्माना वसूल करेगा। दरअसल, एओए फेडरेशन के अधिकारी कई सालों से इंदिरापुरम की सड़कों को अतिक्रमण और जाम मुक्त बनाने की जीडीए से मांग कर रहे हैं। इसके लिए फेडरेशन के पदाधिकारियों ने अस्थाई पार्किंग बनवाकर लोगों को राहत देने की मांग की थी। मगर अधिकारियों ने इस प्रस्ताव में तमाम खामियां और नियमों का उल्लंघन बताकर नकार दिया। अब जीडीए अधिकारियों ने तीन जगहों पर नो पार्किंग जोन बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने शिप्रा मॉल और हैबिटेट सेंटर के बीच जगह को बुधवार से नो पार्किंग जोन बनने पर इसका सख्ती से पालन कराने की बात कही है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से इंदिरापुरम में वाहनों का जाम और अतिक्रमण खत्म कराने के लिए प्लानिंग बन रही थी। इसमें जीडीए के स्टाफ से कई विचार और तरीके सामने आए। जहां उच्च अधिकारियों ने उन्हीं में से नो पार्किंग जोन के प्वाइंट बनाने का फैसला किया है।

Ghaziabad green-lights projects worth Rs 148 crore

GHAZIABAD: Projects worth Rs 148 crore were sanctioned at the infrastructure fund and 14th finance commission meeting of the Ghaziabad Municipal Corporation (GMC) at the district collectorate on Wednesday. The biggest allotment was made to the infrastructure fund – Rs 28 crore for the construction of roads and drains by the public works department. An additional Rs 8.5 crore has been allotted for other construction works. Rs 2.76 crore has been given to the streetlight wing. The health department has been allotted Rs 14.07 crore for buying 50 small loaders for door-to-door collection, 2,000 biometric watches for sanitation workers and field officers, water sprinklers and composting machines, among other equipment. Rs 6.37 crore will be spent on the construction of an RCC stormwater drain from Prahlad Garhi to Vaishali Canal and Rs 3.96 crore on building a drain from Nandgram to Sai Enclave. Horticulture department has been allocated Rs 2.79 crore for buying park equipment.

योगी सरकार ने 10 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

यूपी कैबिनेट बैठक

लखनउ : लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में संविदा पर रखे जाने वाले डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही कुल 10 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।

इन फैसलों पर लगी मुहर

–सोनभद्र के उम्भा गांव के पात्रता रखने वाले लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का प्रस्ताव पास हुआ,कुल 37 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया। –1.68 लाख और लोगों को यूपी में आयुष्मान भारत का लाभ दिया जाएगा। –मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। –संविदा मेडिकल शिक्षकों के वेतन बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। –उत्तर प्रदेश औद्योगिक व सुधार नीति के संबंध में प्रोत्साहन प्रस्ताव पास 2017 की नीति में संशोधन किया जाएगा। –राज्य संपत्ति विभाग द्वारा 16 लक्जरी कारें खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ,15 फार्च्यूनर और 1 इनोवा क्रिस्टा खरीदी जाएगी। –बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव पास हुआ। –सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी और डॉ रहीस सिंह को सूचना सलाहकार के तौर पर 1 लाख रुपये वेतन और 25 हजार आवासीय भत्ता देने का प्रस्ताव पर मुहर। –राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता कराने के लिए कॉलेज परिसर में ही स्थित पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। –एनएचआई दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की गई उनमें अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में कमिश्नर मेरठ के शिकायतों की जांच आख्या पर कार्यवाई का प्रस्ताव पास। –तत्कालीन डीएम गाजियाबाद विमल शर्मा और निधि केसरवानी पर कार्रवाई होगी।

अब अलीगढ़ का नाम बदलने की तैयारी

अलीगढ़ : योगी सरकार के आगरा का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने भी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरीगढ़ करने की बात करना प्रांरभ कर दिया है। अलीगढ़ का नाम बदलने की सबसे पहले कवायद कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री रहते की थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस सरकार होने के चलते मकसद में सफल न हो सके। शहरों का नाम बदलने की कवायद आगरा को अग्रवन करने के साथ फिर से शुरु हो गई है। इसके साथ ही पिछले काफी समय से चली आ रही अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की मांग उठने लगी है। योगीराज में वर्ष 2018 में आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने का प्रस्ताव तैयार करने की तैयारी की गई थी। जिसके साथ ही सांसद सतीश गौतम व शहर विधायक संजीव राजा ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने के मांग शासन स्तर पर की थी। हालांकि सबसे पहले विश्व हिन्दू परिषद ने वर्ष 2015 में अलीगढ़ में एक प्रदेशव्यापी बैठक में प्रस्ताव पास कर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात की थी। भाजपा महानगर उपाध्यक्ष सुबोध स्वीटी ने बताया कि तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने 1992 में मुख्यमंत्री रहते हुए शहर का नाम हरिगढ़ करने कोशिश की थी।

बहुत हो चुका मंदिर–मस्जिद, अब विकास की बात होनी चाहिए : शिवपाल यादव

फिरोजाबाद : प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अयोध्या मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। वहीं प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सोमवार को बांके बिहारी गेस्ट हाउस पर आयोजित पार्टी कार्यकर्ता रघुराज सिंह सविता की बेटी के शादी समारोह में भाग लेने आए थे। जहां वे मीडिया कर्मियों से रुबरू हुए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अयोध्या मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर वर्ग को सम्मान करना चाहिए। शिवपाल ने कहा कि वे पहले से कहते आ रहे हैं कि अयोध्या विवाद का समाधान या तो आपसी समझौते से हो या दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानें। चूंकि अब फैसला आ चुका है जिसें सभी को मानना चाहिए। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल ने कहा कि बहुत हो चुका मंदिर–मस्जिद। अब देश में विकास की बात होनी चाहिए। समाज में अमन–चैन कायम रहना चाहिए। हमारी तो यही प्राथमिकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सरकारी अफसर मनमानी कर रहे हैं। सड़कों के गड्ढे तक अभी नहीं भरे जा सके हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार रोकने में विफल साबित हो रही है।

नोएडा के सैकड़ों फर्जी कॉल सेंटरों से विदेशों तक ठगी जारी

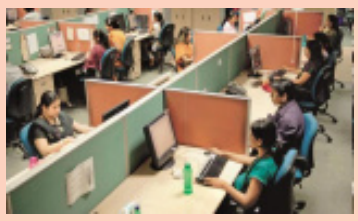

नोएडा : पश्चिमी दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर कनाडा के लोगों से ठगी का मामला नया नहीं है। नोएडा के ऐसे ठगों की तलाश में तो नवंबर 2018 में कनाडा की पुलिस और अमेरिका की एफबीआई की टीम नोएडा तक आ गई थी। उन्होंने करीब सौ से अधिक ऐसे फर्जी कॉल सेंटरों की सूची भी पुलिस को सौंपी थी, जिनके द्वारा अमेरिका और कनाडा में बैठे लोगों से ठगी की गई थी। लेकिन अभी तक भी उनका यह धंधा बदस्तूर जारी है और कॉल सेंटरों के माध्यम से सात समुद्र पार बैठे लोगों को भी ठगा जा रहा है। पुलिस की ही मानें तो यहां पर दो हजार से ज्यादा कॉल सेंटर चल रहे हैं, किस कॉल सेंटर में क्या हो रहा है और कहां पर गलत काम हो

रहे हैं और कहां पर सही, इसके संबंध में एकदम सटीक नहीं बताया जा सकता। लेकिन फर्जी कॉल सेंटर भी यहां से संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से दूर–दराज में बैठे लोगों को ठगा जा रहा है। जिसका खुलासा किसी शिकायत के सामने आने के बाद ही होता है। वहीं एसएसपी वैभव कृष्ण ने कहा कि एफबीआई और कनाडा पुलिस द्वारा जो सूची दी गई थी, उस पर कार्रवाई करते हुए उस दौरान अनेक फर्जी कॉल सेंटरों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा भी पुलिस लगातार कॉल सेंटरों पर कार्रवाई करती रहती है। उनके बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाता रहता है। पुलिस के अनुसार ये लोग विदेश में बैठे लोगों के कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक वायरस पॉप अप भेजते हैं. इसके बाद कम्प्यूटर धीमा हो जाता है. इसके बाद ये ठग उस शख्स को कम्प्यूटर पर वायरस अटैक का मैसेज भेजते हैं। थोड़ी देर बाद इन लोगों को सर्विस मैन का नंबर भेजते हैं. जब पीड़ति उस वायरस को दूर करने के लिए कॉल करता तो ये कॉल नोएडा के इन फर्जी कॉलसेंटर में आती है। इसके बाद आरोपी जालसाज इस वायरस को ठीक करने के नाम पर कम्प्यूटर को रिमोट पर ले डॉलरों में पैसे ठग लेते है।

डेबिट–क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी होने पर भी नहीं डूबेगा पैसा

नई दिल्ली : देश में डेबिट–क्रेडिट कार्ड के चलन ने बड़ी नकदी लेकर चलने की जरूरत को खत्म कर दिया है। लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ इसमें धोखाधड़ी के मामले में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कार्ड को लेकर किसी धोखाधड़ी की स्थिति में उसकी भरपाई बेहद मुश्किल होती है। इस स्थिति में कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (सीपीपी) आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

क्या है सीपीपी

सीपीपी कार्ड का बीमा होता है। एसबीआई सहित कई बैंक अपने कार्ड पर इसकी पेशकश करते हैं। इसके लिए सालाना 900 से 2100 रुपये तक शुल्क वसूलते हैं। इसके तहत क्रेडिट या डेबिट कार्ड को लेकर ऑनलाइन, जालसाजी, एटीएम पिन के जरिए या फिर कार्ड खोने या चोरी होने पर धोखाधड़ी की स्थिति में उसकी भरपाई का कवर शामिल होता है। कार्ड के खोने या चोरी होने के 15 दिन पहले से ऑनलाइन धोखाधडड़ी का कवर उपलब्ध कराया जाता है।

ifjokj dk doj Hkh

कई बैंक बिना शुल्क के आपके परिवार को भी इसमें कवर देने की पेशकश करते हैं। एसबीआई के प्रीमियम कार्ड प्रोटेक्स प्लान में अपने साथ पत्नी को भी कवर में शामिल कर सकते हैं। वहीं इसके प्लैटिनम कार्ड प्रोटेक्शन प्लान में चार लोगों को शामिल कर सकते हैं।

सिर्फ एक कॉल से सभी कार्ड ब्लॉक

कई कार्ड होने की वजह से सभी का विवरण याद नहीं रह पाता है, जिसकी जरूरत कार्ड ब्लॉक करवाने के दौरान होती है। सीपीपी की सुविधा होने पर कार्ड खोने की स्थिति में अलग–अलग बैंकों को फोन करने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस एक कॉल सीपीपी के कस्टमर केयर को करना होता है। वह आपके सभी कार्ड को ब्लॉक करवा देगा।

होटल बिल चुकाती है कंपनी : आप घुमने के लिए परिवार के साथ कहीं गए हैं और वहां कार्ड खो जाए तो वैसी मुसीबत की कल्पना भी शायद आप नहीं करना चाहेंगे। सीपीपी की सुविधा होने पर कार्ड खोने की स्थिति में आपको नकद उपलब्ध कराने के साथ आपके होटल बिल और ट्रेन–हवाई जहाज का टिकट का खर्च भी बीमा कंपनी देती है। एसबीआई सीपीपी सुविधा लेने पर 1.60 लाख रुपये तक का होटल बिल और 1.60 लाख रुपये तक की यात्रा सहायता उपलब्ध कराता है।

iSu dkMZ Hkh nk;js esa-

सीपीपी में पैन कार्ड का कवर भी दिया जाता है। इसके खो जाने पर बैंक बिना शुल्क के इसे बनवाते हैं। आप पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी सीपीपी ले सकते हैं।

संयुक्त आवास आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनी

वसुंधरा : संयुक्त आवास आयुक्त ने मंगलवार को द्रोणागिरी अजपा समिति सोसायटी, वसुंधरा सेक्टर – 11 के लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने समस्याओं को शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया। खुद की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रबंधन समिति का गठन किया है। द्रोणागिरी सोसायटी में संयुक्त आवास आयुक्त अजय कुमार श्रीवास्तव ने अजपा समिति और आवास विकास के बीच विवाद का निपटारे करने की पहल करते हुए बैठक की। पूर्व में भंग की गई प्रबंधन समिति के स्थान पर लोगों की समस्याओं के जल्द से जल्द निपटारे के लिए तैयार नई प्रबंधन समिति का गठन किया गया। प्रबंधन समिति में संयुक्त आवास आयुक्त अजय कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया। अन्य सदस्यों में अधिशासी अभियंता अतुल कुमार, संपत्ति प्रबंधक हेतम पाल सिंह, सरकारी अधिकारी आवास स्वामीदीन चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार एसएस नेगी को भी इस समिति में शामिल किया गया। अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नए प्रबंध समिति के माध्यम से जल्द से जल्द सभी विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों ने कहा है कि गैर सदस्य द्वारा शिकायत करने पर आवास विकास ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस और स्पष्टीकरण के पुरानी समिति को भंग कर दी।

शिक्षक संघ के अध्यक्ष बने डॉ. नीरज तिवारी

साहिबाबाद : लाजपत राय कॉलेज में मंगलवार को शिक्षक संघ का चुनाव हुआ। इसमें अध्यक्ष पद के लिए डॉ नीरज तिवारी, उपाध्यक्ष पद के लिए डॉ प्रेमलता, सचिव पद के लिए डॉ संजीव कुमार, सह सचिव पद के लिए डॉ पीतांबर सिंह चौहान और कोषाध्यक्ष पद के लिए राजेश कुमार शर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया। शिक्षक संघ की बैठक में डॉ अरुण कुमार मिश्रा पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। शिक्षक संघ की बैठक में डॉ विभा गुप्ता, डॉ आरके शर्मा, डॉ सुकेश शर्मा , डॉ एसएम जैदी, डॉ पूनम सिंह, डॉ चेतना मिश्रा , डॉ जया सिंह, डॉ हितेंद्र यादव, डॉ विकास कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया।

27 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त, दो सौ होर्डिंग हटाए गए

साहिबाबाद : नगर निगम की ओर से बुधवार को वसुंधरा व मोहन नगर जोन में प्रतिबंधित सामग्री मुक्त और पर्यावरण क्षतिपूर्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान वसुंधरा जोन में 25 और मोहन नगर में दो किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई। जुर्माना वसूला गया। वसुंधरा जोन में दो सौ अवैध होर्डिंग व पोस्टर हटाए गए। वसुंधरा जोनल प्रभारी सुनील राय की अगुवाई में वसुंधरा व वैशाली में अभियान चला। सुनील राय ने बताया कि दुकानों व होटलों पर छापेमारी कर 25 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई। इनका प्रयोग करने वालों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, तंदूर जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। गंदगी फैलाने वाले पर तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं, बृज विहार व सूर्य नगर में अवैध तरीके से लगे दो सौ अवैध होर्डिंग, बैनर व पोस्टर हटाए गए। सुनील राय ने बताया कि लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जोनल प्रभारी एसके गौतम की अगुवाई में मोहन नगर जोन में अभियान चला। इस दौरान टीम ने दो किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त कर सात हजार रुपये जुर्माना वसूला।

प्रदूषणकारियों की सूचना देने वाले होंगे पुरस्कृत

साहिबाबाद : गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में प्रदूषणकारियों की सूचना देने वालों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। नगरायुक्त दिनेश सिंह ने बताया है कि नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा व पॉलीथिन जलाने व अन्य तरह से पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों की सूचना लोगों से ली जाएगी। लोग जोनल प्रभारी व सफाई निरीक्षकों को इसकी सूचना दे सकेंगे। इसके अलावा नगर निगम के अन्य अधिकारियों को भी सूचना दे सकेंगे। सूचना देने वाले लोगों का नाम गुप्त रखा जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा।

संपूर्ण समाधान दिवस में सात शिकायतों का निस्तारण

गाजियाबाद : जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में तहसील सदर में मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय, एसएसपी सुधीर कुमार सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस में मंगलवार को कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुईं, इनमें से सात शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की आने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता, मानक तथा निर्धारित अवधि के अंदर किया जाए और इसकी सूचना संबंधित तहसील को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया है कि जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का निस्तारण करते हुए यदि शिकायत सही पाए जाए तो संबंधित निस्तारण में शिकायतकर्ता को भी संतुष्ट किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनके गुप्ता, उप जिलाधिकारी सदर आदित्य कुमार प्रजापति, जिला विकास अधिकारी बीसी त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

साइबर क्राइम जागरूकता कार्यशाला आयोजित

इंदिरापुरम : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इंदिरापुरम में मंगलवार को साइबर क्राइम जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीआइएसएफ एनसीआर सेक्टर की ओर से आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन महानिरीक्षक एनसीआर सुधीर कुमार ने किया। आइटी विशेषज्ञ डॉ. नेहा वाजपेयी व काजल कश्यप ने एनसीआर की 24 इकाईयों के 30 राजपत्रित अधिकारियों और 207 अन्य बल के सदस्यों को साइबर क्राइम की जानकारी दी। साइबर क्राइम से बचने के तरीके बताए। इस अवसर पर उप महानिरीक्षक सीजीबीएस नई दिल्ली संजय प्रकाश, रघुवीर लाल आदि मौजूद रहे।

भाजपा महानगर व जिलाध्यक्ष के लिए 34 ने किया नामांकन

xkft ;kckn % भाजपा महानगर अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष पद पर दावेदारों ने जोर–आजमाइश शुरु कर दी है। दोनों पदों के लिए बुधवार को नेहरूनगर स्थित महानगर कार्यालय पर नामांकन प्रक्रिया हुई। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष पद पर 17 व जिलाध्यक्ष पद पर 17 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। दावेदार अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे और सभी ने मजबूत दावेदारी की। दोनों पदों के प्रभारियों ने नामांकन पत्र जमा कर लिए हैं अब इन पत्रों को प्रदेश हाईकमान के पास भेजा जाएगा। वहां से पत्रों की जांच के बाद दोनों पदों के लिए नाम फाइनल होगा। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर अंत या दिसंबर की शुरुआत में महानगर अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष पद पर नामों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं दो दावेदारों पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं वर्तमान क्षेत्रीय मंत्री अजय शर्मा और क्षेत्रीय मंत्री व तीन बार पार्षद रहे पवन गोयल ने नामांकन पत्र वापस कर दिए। बुधवार को नेहरूनगर स्थित भाजपा के महानगर कार्यालय में दो अलग–अलग कक्षों में दोनों पदों के लिए दावेदारों के नामांकन लिए गए। महानगर अध्यक्ष पद के लिए एटा के विधायक विपिन कुमार डेविड प्रभारी थे और उनका सहयोग राखी त्यागी कर रही।

25 नवंबर को चक्का जाम करेंगे ट्रांसपोर्टर

साहिबाबाद : भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर सीमा साहिबाबाद में ट्रांसपोर्टरों व ट्रक ऑपरेटरों की बैठक हुई। बैठक में आगामी 25 नवंबर को होने वाले देशव्यापी चक्का जाम को लेकर रणनीति तय की गई। ट्रांसपोर्टरों व ट्रक ऑपरेटरों ने चक्का जाम में पूरी तरह से शामिल होने का एलान किया। एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी प्रमोद श्योराण ने बताया कि 11 मांगों को लेकर चक्का जाम किया जाए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की मांग है कि एक सितंबर को लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट तत्काल निरस्त किया जाए।

रोडवेज में समय पर नहीं बन रहे स्मॉर्ट कार्ड, यात्री परेशान

साहिबाबाद : रोडवेज यात्रियों को इन दिनों रोडवेज की बसों के लिए स्मॉर्ट कार्ड बनाने में परेशानी आ रही है। वहीं स्मॉर्ट कार्ड आवेदन देने के हफ्तों हफ्तों बाद भी कार्ड बनकर तैयार नहीं हो रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं बसों में सफर के दौरान खुले पैसे ना होने के कारण भी उनको यह कार्ड की अधिक याद आती है। उधर रोडवेज के अधिकारियों कहना है स्मॉर्ट कार्ड बनाने वाली कंपनी से वार्ता कर जल्दी की समस्या को समाधान किया जाएगा। रोडवेज यात्री अशोक ने बताया है कि उन्होंने करीब 20 दिन पहले अपने बेटे के लिए आवेदन किया था लेकिन अब तक कार्ड बनकर नहीं आया है, वहीं मेरठ जाने वाले यामीन ने बताया है कि वह रोजाना मेरठ आते जाते हैं, इसलिए स्मॉर्ट कार्ड बनवाना था ताकि किसी भी बस में कभी भी आपात स्थिति में सफर कर सके लेकिन कार्ड बनने में देरी कारण परेशान होना पड़ रहा है। वहीं रोजाना टिकट लेने के दौरान खुले पैसे की भी दिक्कत आती है इससे परेशानी बढ़ गई है। रोडवेज प्रबंधक अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि इस संबंध में शिकायत मिली है, जल्द ही कंपनी से वार्ता कर समय पर स्मॉर्ट कार्ड बनवाकर वितरित कराए जाएंगे।

EDITORIAL

Quality on tap: On report of Ministry of Consumer Affairs

The report of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution red-flagging tap water quality in major Indian cities comes as no surprise, given that many official water distribution agencies routinely advise consumers to consume only boiled water. Going by the matrix of tests carried out by the Bureau of Indian Standards for the Ministry, Delhi has abysmal water quality, Chennai and Kolkata rank very low, and Mumbai is the only city with acceptable results. City water systems are normatively required to comply with the national standard for drinking water, IS 10500:2012, but most obviously feel no compulsion to do so. Their lack of initiative could be attributed partly to the expanding footprint of packaged drinking water, especially in populous cities, coupled with the high dependence on groundwater in fast-growing urban clusters where State provision of piped water systems does not exist. On paper, the Indian standard has a plethora of quality requirements, including absence of viruses, parasites and microscopic organisms, and control over levels of toxic substances. But in practice, municipal water fails these tests due to the lack of accountability of the official agencies, and the absence of robust data in the public domain on quality testing.

The Centre's approach to the issue relies on naming and shaming through a system of ranking, but this is unlikely to yield results, going by similar attempts to benchmark other urban services. Making it legally binding on agencies to achieve standards and empowering consumers with rights is essential, because State governments would then take an integrated view of housing, water supply, sanitation and waste management. A scientific approach to water management is vital, considering that 21 cities — including many of those found to have unclean tap water — could run out of groundwater as early as 2020, as per a NITI Aayog report. Moreover, the Central Ground Water Board estimates that nearly a fifth of the urban local bodies are already facing a water crisis due to excessive extraction, failed monsoons, and unplanned development. On the issue of regular testing, there is a case to entrust a separate agency with the task in each State, rather than relying on the same agency that provides water to also perform this function. If data on water are made public on the same lines as air quality, it would ratchet up pressure on governments to act. For too long, the response of water departments to the challenge has been to chlorinate the supply, as this removes pathogens, ignoring such aspects as appearance, smell and taste. It is time to move beyond this and make tap water genuinely desirable.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

Look into farmers' issues, DM says in meeting

GHAZIABAD: The district magistrate on Wednesday held a meeting with agitating farmers from Modinagar and discussed with them some of their grievances related to construction of roads and low height of underpasses along the Delhi-Meerut expressway. The DM directed the National Highways Authority of India officials to look into the farmers' problems on a priority basis. Subdivisional district magistrate, Modinagar, Saumya Pandey, has been made the nodal officer to listen to the farmers' grievances and coordinate with NHAI officials to look for a solution.

Woman says cop raped her, threatened to harm family

GHAZIABAD: A 34-year-old woman filed a complaint with the district police chief on Friday, alleging that she had been raped repeatedly by a constable posted at Sahibabad police station. Following the complaint, the constable has been sent to the police lines. The woman, a resident of Sahibabad, said she had written to the SSP's office about the alleged assault on her. According to the complaint, the constable had been raping the woman for the past six months, even though she addressed him as a brother. "I know him for the past seven months, ever since he came to live in the neighbourhood. He would initially address me as sister. But after a while, he started harassing me and touching me inappropriately," she added. The woman alleged that the cop one day barged into her house when her husband and son were away. "He entered my house and raped me. He wanted me to enter into a relationship with him. He said he would kill my son and lodge a fake complaint against me and my husband if I didn't," she alleged.

Woman accuses husband, in-laws of siphoning off Rs 1 cr from her bank account

AGRA: A 39-year-old woman hailing from Noida has registered an FIR against her estranged husband and three in-laws for allegedly siphoning off more than Rs 1 crore from her bank account by forging her signature and misusing her bank documents. A resident of Noida's Sector 50, the woman was married to a Surya Nagar-based resident in 2003. Two years later, the couple had a son. According to the FIR lodged at Hariparvat police station here, in 2011, the woman opened a shoe emporium in Kamla Nagar of Agra from her

savings. While she handled the business operations of her shoe emporium, her brother-in-law and husband took care of all the money transactions even though the bank account of the firm was in her name. Later, the woman came to know about her husband's illicit affairs and drug addiction. When she confronted him, her in-laws allegedly hatched a plan to completely take over her business and oust her from the house. The woman claimed that she had to shut her shoe emporium business on March 31 last year as she was mentally harassed and tortured for money. She claimed that several lakhs of rupees which were to lent to borrowers in the market are yet to be recovered. But before she could take any action to recover the money, her in-laws allegedly evicted her and her 13-year-old son from the house on May 27, 2018, the woman alleged.

19 child labourers rescued, employers to be booked

NOIDA: Nineteen child labourers, working in different establishments under non-hazardous conditions, were rescued on Wednesday from Mamura area under Phase III police station. The labour department said the employers will be booked and fined. Officials said that while eight minors were found working in a boutique where their job was to stitch buttons on garments, other were employed in a dhaba, kirana store and an electrician's shop, and each of them was being paid between Rs 2,000 and Rs 5,000 per month. The anti-human trafficking unit and the labour department were informed after this, Satya Prakash, manager at Childline, told TBC.

Home guard scam probe may be given to CB-CID

NOIDA: The crime branch CID is likely to take over the home guard scam case, with the district police recommending to the state headquarters the transfer of the probe to a higher agency. "The severity and magnitude of the case is quite high and the investigation needs all the details and analysis. We have recommended that the case be transferred to the state CB-CID or any other capable state-level agency, the rest is for the headquarters to decide," Gautam Budh Nagar SSP Vaibhav Krishna told TBC on Thursday. The scam came to light recently after it was found that a few platoon commandants got inflated salaries disbursed for home guards in Gautam Budh Nagar by forging their attendance register. Police suspect the scam, running into crores, was orchestrated by an organised syndicate of platoon commandants overseeing deployment of guards. Surajpur SHO Jitendra Dikhit, the complainant in the case, said the FIR has been lodged on the basis of a complaint received from a platoon commandant on July 17, 2018. Meanwhile, there is panic in the police department with many officials suspecting action on some of the officials posted in the district in the recent past.

Greater Noida drafts policy, activists say build shelters

GNoida: A policy for stray dogs is being finalised for Greater Noida in an attempt to manage the stray dog population in the area, keep rabies in check and bring down instances of conflicts. In the absence of proper infrastructure, the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) had to outsource sterilisation work to NGOs. But the GNIDA ended up paying a higher amount to the NGOs than what the Noida Authority pays (Rs 1,390 for each case), as the strays needed to be transported to sterilisation centres in vans.

Chain snatcher held in Ghaziabad after shootout with police

GHAZIABAD: A bike-borne man, who was fleeing after snatching a gold chain from a woman, was arrested in UP's Ghaziabad after an exchange of gunfire with police, officials said on Saturday. An accomplice of the arrested accused, identified as Raju, managed to flee during the firing on the Richpal Puri-Ganga Water Treatment Plant road on Friday night, SP (City) Manish Kumar Mishra said. The Vijay Nagar police were informed about the snatching incident following which a team set off in pursuit of the two suspects. As the duo sped away on their motorcycle, the rider lost control of the vehicle and both fell down, police said. In a last ditch attempt to escape being arrested, the accused opened fire at the police team. The police retaliated, injuring one of the accused who was shot in the leg, they said. Raju, a resident of Vijay Nagar, was arrested, police said, adding his accomplice took advantage of the commotion and fled. One country-made pistol, two live and as much used cartridges, looted gold chain and the bike used in snatching have been recovered from him, the SP said.

Indraprastha Gas Limited contractor, two others fined for construction

GHAZIABAD: A real estate company, a contractor of Indraprastha Gas Limited and a landowner were fined with Rs 1 lakh each on Saturday for allegedly indulging in construction activities. UPPCB regional officer Utsav Sharma said, "A fine of Rs 1 lakh has been imposed on the builder of SG Alpha in Vasundhara. Likewise, a penalty was imposed on the IGL contractor, DS Enterprises, in Sahibabad for carrying out pipe laying work in the area. The firm had also not taken any permission from the Ghaziabad Municipal Corporation.

Bus with private firm staff rams tractor on NH-9

GHAZIABAD: Nearly two dozen employees of a private textile company were injured after the bus they were travelling in collided with a tractor in Vijay Nagar area on NH-9 on Tuesday morning. According to police, around 8am, the bus driver lost control of the vehicle and hit the tractor carrying material for the construction of a road. The bus used to ferry employees of a private cloth manufacturing company from their home to office in Sector 63. Shyamvir Singh, the SHO of Vijay Nagar police station, said when the cops got information about the accident, a team reached the spot and took the injured to a nearby hospital. Most of the passengers were discharged in an hour after receiving first-aid. However, three people, who were critically injured, were referred to Safdarjung Hospital in Delhi. "Initial investigation revealed that the speed of the bus was over 60km/hr. The driver lost control and descended the bus on the kuchcha road adjacent to the main road and hit the tractor," said the SHO.

Noida Sector 63 gang rape: Family alleges police inaction

NOIDA: The family of the 18-year-old girl who was allegedly gang-raped by five youths in Sector 63 last week has expressed dissatisfaction with the probe, asking why police have failed to arrest the two remaining accused. Officers said the two absconding accused Guddu and Shyam Dikshit were continuously changing hideouts. They said police teams had been sent to Badaun, Hardoi and Saharanpur to catch the two. The girl's brother also sought to know why the authorities at the district hospital were yet to release her sister despite saying she was stable.

Ghaziabad to name, shame 'enemies of environment'

GHAZIABAD: People harming the environment and indulging in banned activities that contribute to pollution in the city will now be named and shamed. District magistrate Ajay Shankar Pandey on Sunday said a board, with the heading 'enemies of the environment', will be displayed at the District Collectorate where names of defaulters, as well as their address and the fines imposed on them, will be mentioned on a daily basis. Such boards will also be displayed in every tehsil, block and ward of the district. The names of the defaulters will also be shared on WhatsApp

and displayed on the district administration's website. Pandey has written to councillors and gram pradhans to look into the pollution-related issues in their areas. He added that legal action will be initiated against those people on whose plots illegal activities are being carried out. "An integrated and detailed plan has been prepared to keep a tab on violators. Councillors and gram pradhans have also been involved. The Ghaziabad municipal commissioner has also been asked to convene a meeting of councillors in this regard. Likewise, panchayat raj officials, sub-divisional magistrates and block development officers have been asked to coordinate with gram pradhans," the DM added. Pandey said various civic agencies, including GMC, Ghaziabad Development Authority, UP Housing and Development Board and Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation, have once again been directed to ensure that garbage or stubble is not burnt in their areas.

Ghazibad cops take ex-SHO into custody, recover Rs 9.8 lakh from factory

GHAZIABAD: Hours after taking former SHO Laxmi Singh Chauhan into custody, Ghaziabad police on Saturday evening raided a defunct steel factory in Link Road area and recovered Rs 9.8 lakh. Inspector Chauhan, accused of stealing Rs 70 lakh from thieves during a probe, had hid the money in that factory, police said. Inspector Chauhan, along with constable Dheeraj Bharadwaj, surrendered in an anti-corruption court in Meerut on November 7. The duo was sent to 14-day judicial custody, but the police took her on a one-day remand for interrogation.

Truck that killed eight of family on EPE identified, search on for driver: Noida Police

NOIDA: The truck that had hit a car on the Eastern Peripheral Expressway (EPE) on Sunday night, leading to the death of eight people, has been identified and efforts are on to arrest its driver, police said. hirteen members of a family, who were travelling in a Maruti Eeco, were returning to Bulandshahr after attending a wedding in Haryana's Ballabgarh. Their car was hit by a "heavy vehicle" near the Sirsa toll plaza on the EPE around 9 pm, they said on Wednesday. Five members of the family, including women and children had died the same night, while three others succumbed to injuries during treatment at hospital. Superintendent of Police, Greater Noida, Ranvijay Singh said, "The erring truck has been identified using footage on Sirsa toll plaza and other subsequent toll plazas in the region." "Multiple teams have been formed to track down the truck and its driver so that suitable action could be taken against him," Singh said. He said Noida Police will also be writing to the National Highways Authority of India (NHAI) and the government to equip the EPE with CCTV camera and other necessary arrangements be also made.

Two 'hypnotise' 66-year-old, rob her

NOIDA: Two men were booked for allegedly posing as beggers, hypnotising a senior citizen and robbing her of her valuables near Atta village on Friday afternoon. The complainant - Narender Dhaka, a resident of Sector 47 - has alleged that his mother Parvati was out shopping in Sector 27 when the two men approached her. "My mother (66) had gone to shop in Atta market and when she was walking back towards the auto stand, the two men hypnotised her and asked her to go with them to a primary school nearby. Later, they took her gold bangles," Dhaka said.

Man stabs wife to death, tries to kill self

GHAZIABAD: A 25-year-old man allegedly stabbed his wife to death and then attempted suicide by injuring himself with the same knife in Kotwali's Balupura area on Monday afternoon. The injured couple was taken to MMG District hospital by locals where doctors declared the woman dead and referred the man to GTB hospital in Delhi. Police said the case was found to be related to dowry harassment. The woman Pooja (23) was a resident of Kallpura area. She married Vikas, an auto-rickshaw driver and a resident of Gukhna, on December 14, 2015, said police. Pooja's father Surendra Kumar, an e-rickshaw driver, alleged that soon after the marriage, Vikas started demanding a motorcycle and Rs 30,000 from him and when he could not fulfil his demands, the latter started torturing his daughter. "Vikas quarrelled a lot with Pooja over dowry. When the dispute between them increased, I complained about it in the arbitration cell in October 2016.

Wider NH-9 sees 25% of all traffic fines in Ghaziabad

GHAZIABAD: A wider NH-9 is good news for traffic. But the high-speed corridor connecting Delhi and Ghaziabad that is being widened into India's first 14-lane highway is also seeing traffic violations galore. This inference can be drawn from recent challan data of Ghaziabad traffic police — of over 2.75 lakh vehicles prosecuted by the cops for road rule violations from January to October this year, some 25% were challaned on NH-9 alone, with wrong-side travel, speeding, driving without seatbelt and riding without helmet being the major offences. The latest accident on this highway occurred on Tuesday when nearly two dozen employees of a private company were injured after the private bus in which they were travelling collided with a tractor in Vijay Nagar where the highway is now wider than it has ever been. The other two highways — NH-91 and NH-58 — that pass through the city are equally accident-prone. In fact, the traffic police have identified over 15 black spots on these three highways, including Lal Kuan intersection, Kala Patthar in Indirapuram, Mohan Nagar and Ganga Canal in Muradnagar. According to traffic police data, between January and September this year, as many as 694 accidents happened in Ghaziabad, including on these three highways, in which 298 people died and 474 sustained injuries. In 2018, the number of accidents reported in the city was 672, in which 310 people died and 602 were injured. Two-wheelers topped the list of those challaned for breaking traffic rules. Of the 2,75,962 challans issued between January and October this year, some 1.84 lakh were against bikers, followed by cars (63,358), three-wheelers (18,133), trucks (9,288), buses (611) and tractors (45). Of the bikers, 1.21 lakh were challened for riding without a helmet. Similarly, 24,450 people were fined for driving without seat belts and 6,100 for wrong-side driving, according to this year's data. Pramhansh Tiwari, traffic inspector, said dangerous driving, stunts by youths and underage driving also figure in the challans. "We have issued 1,036 challans for dangerous driving, 57 for road stunts, and 48 for underage driving. Similarly, 2,428 commuters were fined for using cell phones and 35 for drunk driving during this 10-month period."

Paid extra yrs ago, buyers of GNIDA plots to get refund

Greater Noida: Thousands of people who had purchased a house or a plot from the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) are likely to get refunds. During an internal audit, it was found that 5,520 buyers had ended up paying extra to the Authority. These buyers had invested in housing schemes or plots launched almost a decade back in sectors 2 and 3, MU-01, XU-01, 02, 03, Omicron-01, 02, 03 and 01A of Greater Noida. Between 2007 and 2008, Greater Noida started seeing aggressive development and the authorities began acquiring land. But a protest by

farmers over additional compensation stalled the land acquisition process in 2011. Over 450 petitions were filed in the Allahabad high court, and it awarded 64.70% additional compensation to the agitating farmers. Following the Gajraj case order, GNIDA issued notices to buyers saying they needed to pay extra and the money would be used to pay compensation to farmers.

Noida gang-rape case: Opposition hits out at BJP government on safety

NOIDA: Opposition parties on Saturday attacked the BJP government in the state over deteriorating law and order, referring to the alleged gang rape of an 18-year-old girl in a green stretch in Sector 63 last Wednesday. Functionaries of Congress, Samajwadi Party and Aam Aadmi Party demanded that police intensify patrolling across Gautam Budh Nagar district and sought installation of CCTV cameras and lights along all roads. The girl was discharged from the district hospital on Saturday. Chief medical superintendent Vandana Sharma said she was stable. On Wednesday, the girl was called to a secluded place in Sector 63 by an acquaintance named Ravi, who had promised her a job in the company where he worked as a clerk. Ravi allegedly forced himself on the girl, prompting her to raise an alarm. Two youths rescued her from Ravi and forced him to flee. But instead of escorting the girl to safety, the duo called three of their friends and allegedly took turns to rape her. Congress alleged that a delegation of women functionaries was barred from meeting the family of the girl on Saturday.

Ghaziabad sees three houses on average getting burgled every day

GHAZIABAD: Be wary about how you lock your house as there are chances that you might be the next target for thieves on the prowl in Ghaziabad. Over the last few years, the district has witnessed a rising number of thefts. According to police data, while 492 cases were reported in 2015 the figure increased to 760 in 2018. However, in 2019, the number skyrocketed. Between January and October this year, 975 cases of theft have already been reported, meaning more than three cases (on average) every day. The police said that this year, they have arrested 55 thieves from the district and sent them to jail. Officials said around 30% of the theft cases were lodged by residents of highrise apartments while the rest of them came from independent houses, colonies and factories. Around 20% of cases were lodged against the house helps or other staffers, the cops said. In the 2,383 cases of theft that were reported between 2015 and 2018, assets worth over Rs 1 crore were stolen. "A number of crimes can be avoided if residents are vigilant and proactive about them. People should install CCTV cameras around their houses and when they go out, they should properly lock their homes," a senior cop said. In 2018, former SP (city) Shlok Kumar had issued guidelines to apartment owners associations (AOAs) and RWAs to strengthen their security mechanism. Besides, residents also have the option to install anti-theft devices in their flats. Sudhir Kumar Singh, senior superintendent of police (SSP) Ghaziabad, told TBC that the cases of theft have gone down in the last two months as police have arrested several criminals. "Nowadays, it is very easy to enter any house on the pretext being a worker, a house help and more. So police verification is very important for these things. The police verification forms can be filed online," Singh said. Police said that patrolling, especially during the night has been enhanced, but AOAs and RWAs should come forward and plug the gaps in their society's security. "I have formed a team at every police station to keep an eye on suspicious persons. The teams also check the vendors and workers who work in highrises," he added. Among the prominent theft cases in Ghaziabad is the one that took place in August. Four persons, including the driver of a businessman, were arrested for allegedly stealing cash and jewellery worth Rs 1.2 crore from his Kavi Nagar house.

हेल्प लाईन नंबर

गाजियाबाद प्रशासन

डीएम – 2824416
आवास – 2820106
एडीएम (सिटी) – 2828411
एडीएम (प्रशासन) – 2827016
सिटी मजिस्ट्रेट – 2827365
आयकर विभाग– 2714144
पासपोर्ट कार्यालय– 2721779

पुलिस अधिकारी

एसएसपी –2820758,9643322900
पुलिस अधीक्षक नगर–2854015
पुलिसअधी. यातायात–2829520
सीओ प्रथम– 2733070
सीओ द्वितीय – 2791769
सीओ एलआईयू– 2700925
सीओ लोनी– 3125539

जीडीए

उपाध्यक्ष जीडीए – 2791114
जीडीए सचिव – 2790891

अस्पताल

सी.एम.ओ. – 2710754
सी.एम.एस. – 2730038
आपातकालीन – 2850124
कोलम्बिया एशिया –3989896
यशोदा अस्पताल–2750001–04
गणेश अस्पताल –4183900
संतोष अस्पताल –2741777
सर्वोदय अस्पताल –2701694
नरेन्द्र मोहन अस्पताल 2735253
जिला अस्पताल(एम्बुलेंस) 2730038
यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस) 2701695
पुष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल 4188000
पुष्पांजली मेडिकल सेन्टर 43075600

बीएसएनएल

आदेश कुमार (जीएम) 2755777

अग्निशमन विभाग

नगर कन्ट्रोल रूम – 2734906
कोतवाली – 2732099
जिला कन्ट्रोल रूम –2766898

पुलिस स्टेशन

एसएचओ इंदिरापुरम–संदीप कुमार सिंह– 9643322921
एसएचओ लिंक रोड– लक्ष्मी सिंह चौहान– 9643322924
एसएचओ–साहिबाबाद– जितेंद्र कुमार सिंह– 9643322923
एसएचओ खोड़ा– सतेंद्र प्रकाश– 9643322922
कोतवाली – 2732088
सिहानी गेट – 2791627
कविनगर – 2711843
विजयनगर – 2740797
इंदिरापुरम – 2902858
लोनी – 2600097
अग्निशमन विभाग –2732099 9818702101
रेलवे इन्कवायरी –131

नगर निगम

नगरायुक्त– 2790425,2713580

विद्युत विभाग

मुख्य अभियंता – 2821025

पूछताछ

रेलवे कस्टमर –2797840, 139
रिजर्वेशन – 8888
रोडवेज इन्कवायरी –2791102

प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
Phone No.: 0120-4561000

Girl students to be in-charge of police stations for a day

GHAZIABAD: Police in Ghaziabad will soon start an initiative in which it will give charge of a police station to a schoolgirl for a day. The police department is drawing up the criteria for selection of students for this. The move came after the Federation of apartment owners' association (AOA) wrote to Uttar Pradesh DGP to invest in building a friendly relationship between police and women citizen. "The aim of this movement is to help women students file any complaint of crime against them without fear of police," a member of the AOA federation said. Federation members also said that usually girls fear to report any crime to the police due to which many crimes go unreported. FedAOA founder Alok Kumar said, "I am suggesting the police to conduct a quiz and debate programmes in schools, the winner of which will be appointed as in-charge of a police station for a day." "A few girl students will be selected from across all the schools of the district on a set of criteria and they will be given training on policing in the state.

Bike Bot kingpin booked after row in Surajpur district court

GNOIDA: The main accused in the Bike Bot scam, who is already in jail for allegedly duping 2.4 lakh investors on the pretext of promising them lucrative returns, was booked for allegedly creating a ruckus in Surajpur district court on Saturday. The incident took place when the accused, Sanjay Bhati, was brought in court for a hearing and he had an argument with some of the investors. He allegedly threatened some of the investors and also used a mobile phone, despite being stopped by the police.

After three-year delay, construction work of Delhi Metro's Phase IV to finally begin this month

NEW DELHI: After a delay of more than three years, construction of Delhi Metro's Phase IV project is finally going to start by the end of this month. The first civil contract of Delhi Metro Rail Corporation's (DMRC) Phase IV project has been awarded for the construction of a portion of Janakpuri West – R K Ahsram Marg corridor, which is an extension of the Magenta Line (Botanical Garden-Janakpuri West). The contract includes construction of a portion of the Janakpuri West – R K Ahsram Marg corridor with ten stations - Keshopur, Paschim Vihar, Peeragarhi, Mangolpuri, West Enclave, Pushpanjali, Deepali Chowk, Madhuban Chowk, Prashant Vihar and North Pitampura. This was also the first Phase IV tender to be floated by DMRC. "The given work involves the part design and construction of elevated viaduct, elevated ramp, siding line and station buildings," a DMRC spokesperson said. "The work on this corridor is expected to commence by end of November and is scheduled to be completed within 30 months from the commencement," he said.

Builders, buyers, Rera officials... all wait for UP relief

NOIDA: A week since the UP chief minister promised an "announcement" for the real estate sector in the first National Rera Conclave held in Lucknow on November 4, builders and buyers are still waiting for it. Chief minister Yogi Adityanath had said at the conclave, "Within a week we will come up with an announcement which would help reinstate the faith of all stakeholders in the real estate industry and Uttar Pradesh government's seriousness about it." We are waiting for their decisions eagerly," UP-Rera member Balwinder Kumar said.

Cops ran up food bills of Rs 17 lakh, never paid up: Eatery owners

GHAZIABAD: The image of the authoritarian cop throwing his weight around while those around scramble to appease him is an all too familiar one. In Ghaziabad, a group of eatery owners decided to put an end to this narrative of "extortion". "Around Diwali, the station house officer of every police station in the district held meetings with the owners of restaurants and hotels, telling them that encroachment and parking violations would lead to strong action. Just a day after that, eatery owners started getting calls from police officers in every police station, ordering more than 100 packs of sweets

and the same number of dry fruit packs," said Anil Kumar Gupta, the president of the Association of Food Operators in Ghaziabad. There are 17 police stations in Ghaziabad. The Association of Food Operators alleged every police officer ran up bills of Rs 1-1.5 lakh. Initially, Gupta said, the police officers said that they would pay the bills but when they were asked for the money later, they threw their weight around and threatened them about encroachment and parking. "Then they came with families and friends for lunch and dinner, and never paid those bills either," he added. For most eatery owners, they said, the sequence of events is not unfamiliar. "Restaurant and hotel owners are harassed by police at every level all the time. They often ask that the food they order be provided free of cost or at half price," Gupta said. What is not familiar, though, is the scale. And eatery owners decided to resist it this time. The Association of Food Operations has more than 150 members in Ghaziabad.

BJP MLA among four injured as car flips on Yamuna Expressway

GNOIDA: Four men, including a BJP MLA, were injured after their car overturned on Yamuna Expressway near Rabupura police station on Monday. The victims have been identified as Vinod Katiyar, member of the Legislative Assembly in Bhognipur constituency of Kanpur Dehat, his driver Anuj and two guards Satendra Singh and Mohammad Mukhtar, police said. The incident happened at 3.45 am when they were returning home from a wedding in Noida. "We received a PCR call about the accident following which a team was sent to the spot.

Tip-off Noida administration via WhatsApp about stubble burning, get reward

NEW DELHI: IIT Delhi started providing Central Pollution Control Board with pollution projections and possible measures Delhi's civic bodies could undertake every fortnight from September. These so-called 'biweekly plans', however, pertained only to the capital because gaps in emissions inventory data from various sources prevented the extension of the exercise to most other NCR cities. IIT Delhi, has therefore, requested CPCB to set up an emissions inventory cell to provide accurate and updated data related to each source of pollution across NCR. Harsha Kota, assistant professor of civil engineering at IIT Delhi, who specialises in developing air quality models, explained that the plans forecast the levels of pollution in the coming fortnight and the steps to be taken to tackle the problem. However, she told TBC, "If we don't have the complete data from the emissions inventory, we will be unable to analyse information effectively or forecast the top contributing source for the fortnight." IIT Delhi currently uses the emissions inventory data of the Union ministry of earth sciences.

Two found transporting calf remains held and booked; knife, rope found

NOIDA: Two men have been arrested for allegedly killing a calf with a knife near the burial ground in Sector 38 around 3am on Thursday. The men, along with two others who managed to flee, were allegedly found transporting the remains of the animal. The cops identified the four men as Nazim Ahmed, Farman, Naushad and Kameel. Acting on a tip-off, a team of police arrived near the burial ground around 3:30 am and allegedly spotted an autorickshaw in which the accused had kept the remains of the calf.

No food, medicines for 2 months, crisis at only Noida animal shelter

NOIDA: The only animal shelter in Noida and Greater Noida is reeling under severe shortage of supplies as the Noida Authority has nearly stopped sending animal food, medicines and cleaning items for the past two months, according to volunteers who have now taken to social media to voice their concerns. The Sector 94 shelter is home to nearly 1,400 animals and birds. Staff at the shelter said the last batch of antibiotics came in August and food was supplied in September in small batches. But it all got exhausted a week back. Despite reminders and a visit by the officer on special duty earlier this week, the situation hasn't improved yet. "We have been visiting the shelter regularly and we found that food and medicines are not there at all. There is almost no food for larger animals. Sanitary equipment and other supplies, like gas cylinders, are exhausted. I have got a cylinder arranged and other volunteers are now helping with food," said Anuradha Dogra, a volunteer and a member of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA). The Noida Authority had taken over the administration of the animal shelter from the SPCA about two years ago.

161 गांवों के विकास में बाधा बने 40 विभागों पर होगी कार्रवाई

गाजियाबाद : जनपद के 161 गांवों के विकास में रोड़ा बने 40 विभाग पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इन विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीडीओ ने कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी है। दरअसल , अंत्योदय योजना के तहत विकास कार्यों का सर्वे किया गया था। यह सर्वे संबंधित विभागों द्वारा सत्यापन किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड कर फंड की मांग की जानी थी। मगर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विभाग इसका सर्वे का सत्यापन नहीं कर रहे हैं। इससे गांवों का विकास कार्य अटका हुआ है।

एक भूमि की कई बार रजिस्ट्री नहीं कर सकेंगे भूमाफिया

गाजियाबाद : भूमि की रजिस्ट्रियों में हो रही गड़बड़ी व छोटे भूमाफिया पर काबू पाने के लिए जिले में जल्द अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बड़े भूमाफिया के साथ अब छोटे भूमाफिया पर भी शिकंजा कसा जाएगा। छोटे भूमाफिया एक प्लॉट की कई–कई बार रजिस्ट्री कर लोगों को चूना लगाते हैं। अब ऐसे भूमाफिया को प्रशासन रडार पर लेने जा रहा है। रजिस्ट्रार कार्यालय से ऐसे भूमाफिया की कुंडली खंगाली जाएगी और इन पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के ऑपरेशन क्लीन के तहत प्रशासन ने यह योजना तैयार की है। अब जल्द ही ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा। अब से पहले सरकारी व निजी भूमि पर कब्जा करने वाले भूमाफिया चिह्नित किए जाते थे लेकिन अब छोटे भूमाफिया भी प्रशासन के शिकंजे में होंगे। बता दें कि जिले में लंबे समय से भूमाफिया सक्रिय हैं। खासतौर पर लोनी, खोड़ा व विजयनगर में इनकी सक्रियता सबसे अधिक है। भूमि की खरीद–फरोख्त में ये लोग फर्जीवाड़ा कर आम आदमी को जमकर ठग रहे हैं। इनके साथ सरकारी अमला भी शामिल है। भूमाफिया पर शिकंजा कसने व उनके साथ मिले हुए लोगों को चिह्नित करने के लिए जिलाधिकारी ने योजना तैयार की है। इसके तहत भूमाफिया को चिह्नित करने के साथ इनका सरकारी सिस्टम द्वारा मदद करने वाले विभागों और अधिकारियों को निशाने पर लेने का काम शुरू किया गया है। इस अभियान में सबसे अधिक सक्रिया भूमिका सब–रजिस्ट्रार कार्यालय की होगी। इस संबंध में एक बैठक में जिलाधिकारी ने सब–रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही पावर ऑफ अटॉर्नी से होने वाली रजिस्ट्री पर भी खास निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने पाया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ही फर्जीवाड़े में सबसे अधिक गड़बड़ी होती है। जिले में वर्तमान में 558 हेक्टेयर भूमि पर भूमाफिया का कब्जा है।

ढाई लाख से अधिक लोग सीओपीडी से ग्रस्त

गाजियाबाद : डायबिटीज की तरह सीओपीडी (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) भी यानि फेफड़ो से संबंधित प्राणघातक बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सीओपीडी का मुख्य कारण धूमपान के साथ ही वायु प्रदूषण भी है। खासकर सर्दी के साथ ही परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। आइएमए की मानें तो गाजियाबाद में ही ढाई लाख लोग इसकी चपेट में है। लोगों को जागरूक करने के लिए आइएमए भवन में कार्यशाला आयोजित की गई। हर वर्ष नवंबर माह के तीसरे बुधवार को विश्व सीओपीडी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

टोल टैक्स की दरें जनवरी से कम करने की तैयारी

गाजियाबाद : देशभर के सभी टोल प्लाजा पर अगले साल जनवरी से टोल टैक्स की दरें कम हों जाएंगी। इसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय टोल नियमावली में बदलाव करने जा रहा है। मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह बदलाव केवल एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के लिए लागू होगा। सामान्य सड़क के टोल टैक्स में कमी नहीं होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय टोल टैक्स की दरों में कटौती करने जा रहा है। इसके लिए एनएचएआई अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अधिकारी ने

बताया कि मौजूदा समय में स्ट्रक्चर की लंबाई की गणना का दस गुणा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। नए नियम के अनुसार, अब स्ट्रक्चर की लंबाई की गणना का पांच गुना टैक्स वसूला जाएगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे के पिलखुवा में साढ़े चार किलोमीटर एलिवेटेड रोड है। दस गुणा के हिसाब से एलिवेटेड रोड की लंबाई 45 किलोमीटर बैठती है। वाहन चालकों से सामान्य सड़क के अलावा 45 किलोमीटर का टोल टैक्स एलिवेटेड रोड का लिया जा रहा है। नए नियम में अब स्ट्रक्चर की लंबाई की गणना का पांच गुणा टैक्स वसूला जाएगा। इस हिसाब से पिलखुवा टोल पर लोगों को सामान्य सड़क के अलावा 22.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का टोल टैक्स देना होगा। इसी तरह की व्यवस्था सभी टोल प्लाजा पर होने जा रही है। एनएचएआई, दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे के परियोजना निदेशक आरपी सिंह ने बताया कि दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले सप्ताह में टोल के नए नियम लागू होंगे। इससे टोल दरों में कमी की जाएगी। इसके बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी।

एक दिसंबर से महंगी हो जाएगी फोन कॉल, बढ़ जाएंगी वोडा–आइडिया और एयरटेल की दरें

नई दिल्ली : वित्तीय संकट के मद्देनजर दूरसंचार कंपनी वोडाफोन–आइडिया और एयरटेल ने एक दिसंबर से अपनी मोबाइल सेवा की दरें बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों कंपनियों ने सोमवार को यह घोषणा की। वोडाफोन–आइडिया ने अपने बयान में कहा, अपने ग्राहकों को वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है। किसी भारतीय कंपनी का एक तिमाही में यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। वहीं, दूरसंचार क्षेत्र की एक अन्य दिग्गज कंपनी एयरटेल

अपने कारोबार को व्यवहारिक बनाने के लिए दिसंबर से अपनी मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ाएगी। भारती एयरटेल ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 23,045 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह मानती है कि दूरसंचार नियामक ट्राई भारतीय मोबाइल क्षेत्र में मूल्य निर्धारण में तर्कसंगत व्यवहार लाने के लिए सलाह– मशवरा की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली

गाजियाबाद : तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र–छात्राओं ने कविनगर रामलीला मैदान से पुराना रोडवेज बस अड्डा तक यातायात जागरूकता रैली निकाली। रैली को एसपी ट्रेफिक श्याम नारायण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोडवेज बस अड्डा में सभी स्कूली बच्चों को जादू दिखाकर यातायात नियमों को अपनाने की प्रेरणा दी गयी। इस दौरान हाथों में यातायात जागरूकता के बैनर व तख्ती लेकर नारे लगाते हुए नियमों के पालन करने की अपील की गई। रैली में एआरटीओ आरके सिंह, राजेश सिंह, अमितराजन राय, सीओ ट्रैफिक महीपाल सिंह, टीआई परमहंस तिवारी, एनसीसी कैडेट, स्कूली बच्चों व नागरिकों ने प्रतिभाग किया।

पैसेफिक मॉल पर 26 लाख का जुर्माना

गाजियाबाद : प्रदूषण फैलाने वालों पर बुधवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। भारी उर्जा के जेनरेटर चलाने व निर्माण कार्य होता हुआ पाया जाने पर प्रशासन ने पैसेफिक मॉल पर 26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मॉल प्रबंधन के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही नंदग्राम में मिट्टी की खोदाई व खरीद–फरोख्त पाए जाने पर प्रशासन ने संबंधित के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए मौके से एक जेसीबी व तीन खाली ट्रैक्टर–ट्रॉली बरामद की हैं। इसके साथ ही जिले में प्रदूषण की रोकथाम के लिए अन्य कई कार्रवाई की गई हैं।जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि उनके वाट्सएप पर किसी ने जानकारी दी कि कौशांबी स्थित पैसेफिक मॉल व नंदग्राम में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इस पर उन्होंने एसडीएम सदर आदित्य प्रजापति, अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय खालिद अंजुम व क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी के निर्देशन में टीमों का गठन कर विभिन्न स्थानों पर भेजा। टीमों ने संयुक्त रूप से पैसेफिक मॉल का निरीक्षण किया तो मौके पर बेसमेंट में 1250 केवीए के पांच ऑटोमेटिक डीजल जेनरेटर पाए गए। मौके पर मौजूद जेनरेटर ऑपरेटर ने बताया कि बिजली जाने के बाद इन जेनरेटरों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने मॉल प्रबंधन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा मॉल में निर्माण कार्य भी होता हुआ पाया गया, इस पर निर्माण कार्य को बंद कराने के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मौके पर जेनरेटर लगाने व शांति व्यवस्था भंग करने पर मॉल के एजीएम रूपेश कुमार श्रीवास्तव, मैनेजर वरुण सक्सेना व अरुण कुमार के खिलाफ धारा 151 के अंतर्गत निरुद्ध किया गया। डीएम ने बताया कि पैसेफिक मॉल के मालिकों पर कार्रवाई के लिए विधिक राय ली जा रही है।

BUREAU OFFICE
PRATEEK BHARGAVA
Bureau Chief
5, Ashok Vihar, 3rd Floor,
GMS Road, Nr. Ballupur
Chowk, Dehradun.
Mobile: +91 8130640011
Email: prateekb@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release and Advertisements

BUREAU OFFICE
VIKRAM KUMAR
Bureau Chief
12/516, Friends Co-operative
Society Vasundhra,
Ghaziabad (UP)
Mobile: +91 8130640077
Email: vikram@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release and Advertisements

Printed and Published by Dheeraj Kumar Bhargav at B.F.L Inrotech Ltd, C-9, Sector-3 Noida, Distt. Gautam Budh Nagar and Published at 282, Sarai Nazar Ali, behind MMG Hospital Ghaziabad (U.P.) 201 001. Editor: Dheeraj Kumar, Resident Editor : Manisha Bhargava** Email: editor@tbam.co.in **(RNI. No) : UPBIL / 2009 / 28691 Postal Registration No. UP/GBD-80/2016- 18.** Advertisement : Ph. No. : 0120-2850800, 2850297, Fax : 0120-4561000 at 67, 1st Floor, Richpal Puri, Hapur Road, Ghaziabad (U.P.)** Responsible for selection of News under the PRB Act. Reproduction in any manner, electronic or otherwise in whole or in post without prior written permission is prohibited.